

## संतुलन की ओर कदम: अंतरराज्यीय जल वविवाद

यह एडिटरियल 25/07/2023 को हद्दिसतान टाइम्स में प्रकाशित [“An equitable and long-lasting way to resolve inter-state river water disputes”](#) लेख पर आधारित है। इसमें अंतरराज्यीय जल वविवाद समाधान से संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है और वचिार कथिा गया है कि संसाधनों के न्यायसंगत साझेदारी से कैसे इन वविवादों को सुलझाने में मदद मलि सकती है।

### प्रलिमिस के लयि:

[अंतरराज्यीय जल वविवाद, अंतरराज्यीय नदी जल वविवाद \(ISRWD\) अधनियम 1956, महानदी जल वविवाद, कृषणा नदी जल वविवाद, कावेरी नदी जल वविवाद, हेलसकिी नयिम 1966, जल संसाधन पर बर्लनि नयिम, 2004](#)

### मेन्स के लयि:

अंतरराज्यीय जल वविवाद और समाधान

जीवकिा और वकिास के लयि जल संसाधनों से जूझ रहे वशिव में पर्याप्त जल उपलब्धता तक न्यायसंगत पहुँच एक गंभीर चतिा का वषिय बनी हुई है।

भारत जैसे वविधितापूरण और बड़ी आबादी वाले देश में [अंतरराज्यीय नदी जल वविवाद](#) बार-बार उत्पन्न होने वाली चुनौती रही है, जसिसे वभिन्न कृषेत्रों के बीच तनाव बढ़ रहा है और प्रगति में बाधा आ रही है। ये वविवाद केवल राजनीतिक ही सीमति नहीं हैं बल्कि प्रायः [सामाजिक जीवन और वमिर्श में भी](#) फैल जाते हैं। इस परदृश्य में इस मुद्दे का स्थायी समाधान ढूँढना आवश्यक हो गया है जो जल संसाधनों के उपयोग में देरी, लागत में वृद्धि और कभी-कभी वधि-व्यवस्था की समस्याओं का कारण बनता है।

नदी जल का न्यायसंगत बँटवारा न केवल समुदायों और कृषि की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूरति के लयि आवश्यक है बल्कि [सामाजिक न्यायसंगत अंतरराज्यीय संबंधों और सतत् वकिास को बढ़ावा देने के लयि भी महत्त्वपूरण है।](#)

## भारत में अंतरराज्यीय जल वविवादों का वर्तमान परदृश्य:

### ■ वविवाद में शामिल राज्य और नदयिाँ:

- हाल ही में [कर्नाटक और तमलिनाडु के बीच पेन्नैयार नदी वविवाद](#) चर्चा में रहा। इसके बाद [महादयी नदी वविवाद](#) पुनः चर्चा में आया जो लंबे समय से कर्नाटक और गोवा के बीच वविवाद का वषिय रहा है।
- [सतलुज-यमुना लकि नहर, कृषणा जल वविवाद \(आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक\), महानदी जल वविवाद \(ओडिशा और छत्तीसगढ़\) और कावेरी जल वविवाद \(तमलिनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी\)](#) जैसे अन्य कई जल वविवाद प्रायः खबरों में आते रहते हैं।

### ■ जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- जल (यानी जल आपूरति, सचिाई, नहर, जल नकिासी, तटबंध, जल भंडारण और जल वदियुत) [राज्य सूची \(State List\)](#) में शामिल वषिय है।
- [संघ सूची \(Union List\)](#), केंद्र सरकार को संसद द्वारा घोषति सीमा तक अंतरराज्यीय नदयिाँ/घाटयिाँ को वनियमति/वकिासति करने का अधकिार प्रदान करती है।
- [अनुच्छेद 262](#) के अनुसार, [अंतरराज्यीय नदी जल वविवाद \(inter-state river water disputes- ISRWD\)](#) के मामले में संसद वधिा द्वारा [नमिनलखिति के लयि उपबंध](#) कर सकती है:
  - कसिी भी वविवाद के अधनिरिणयन के लयि
  - कसिी अंतरराज्यीय नदी/घाटी के जल के वतिरण/नयितरण के लयि
  - किकोई भी न्यायालय ऐसे कसिी भी वविवाद या शकिायत के संबंध में कृषेत्राधकिार का प्रयोग नहीं करेगा।

### ■ अंतरराज्यीय नदी जल वविवाद (ISRWD) अधनियम, 1956:

इस अधनियम के तहत यदि वविवाद में संलग्न राज्य बातचीत से मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं हैं तो केंद्र [ISRWD को हल करने के लयि एक न्यायाधकिरण \(tribunal\) का गठन करता है।](#)

- सरकारयिा आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं को शामिल करने के लयि इसे [वर्ष 2002 में संशोधति कथिा गया।](#)

Tribunal	Year of Formation	States Involved	Current Status	Awards
Krishna Water Disputes Tribunal II	2004	Andhra Pradesh, Maharashtra, Telangana & Karnataka	Tribunal Term extended	Award given 2013. Some matters subjudice
Mahanadi Water Disputes Tribunal	2018	Chhattisgarh & Odisha	Tribunal Exists	Matter under adjudication
Mahadayi Water Disputes Tribunal	2010	Karnataka, Goa & Maharashtra	Tribunal Exists	Award given 2018. Some matters pending
Ravi & Beas Water Tribunal	1986	Rajasthan, Haryana & Punjab	Tribunal term extended	Matter subjudice
Vansadhara Water Disputes Tribunal	2010	Odisha & Andhra Pradesh	Tribunal dissolved 2022	Yet to be published

## ISRWD न्यायाधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण की राह की चुनौतियाँ:

- गठन संबंधी चुनौतियाँ: ISRWD के नरिणय के लिये एक न्यायाधिकरण का गठन तभी कया जाता है जब इसके लिये केंद्र सहमत हो।
  - वर्तमान में सभी पक्षों के लिये स्वीकार्य जल डेटा की अनुपस्थिति के कारण अधनिरिणय के लिये आधार रेखा नरिधारति करना कठनि हो गया है।
- वर्तमान तंत्र से संलग्न समस्याएँ: इन न्यायाधिकरणों के वर्तमान तंत्र में ISRWD न्यायाधिकरण के नरिणय को लागू करने में लंबी देरी और गैर-अनुपालन जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।
  - भारत में गोदावरी और कावेरी जल वविादों जैसे वविादों को समाधान पाने में लंबी देरी का सामना करना पड़ा है।
  - इसके अलावा, प्रायः संलग्न पक्षकार न्यायाधिकरण के नरिणय से संतुष्ट नहीं होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँच जाते हैं, जिससे वाद/मुकदमेबाज़ी के एक और दौर का आरंभ हो जाता है।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव: व्यापक रूप से माना जाता है कि अधनिरिणय ISRWD को नपिटाने का उपयुक्त तरीका नहीं है। ऐसे कई वविादों में वधि के प्रश्न शामिल नहीं होते, बल्कि जल वविज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, कृषि, जलवायु, समाजशास्त्र आदिके दायरे में आने वाले वषिय शामिल होते हैं।
  - इस प्रकार, एक और पहलू जिसकी इन न्यायाधिकरणों में कमी है, वह है वविादों को वैज्ञानिक तरीके से नपिटाना।
- ISRWD के समाधान की राह की अन्य चुनौतियाँ:
  - डेटा साझेदारी और वविाद में संलग्न राज्यों के बीच डेटा की वसिंगतियाँ जैसी चुनौतियाँ भी प्रायः मौजूद होती हैं।
  - राजनीतिक दल प्रायः इन वविादों का राजनीतिकरण कर देते हैं जिससे मुद्दे पर नषिपक्षता से वधिार करना और सर्वसम्मति-आधारति समाधान ढूँढना कठनि हो जाता है।
  - जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल की बढ़ती मांग जल संसाधनों के लिये राज्यों के बीच प्रतसिपर्द्धा को तेज़ करती है।
  - जल एक अत्यधिक भावनात्मक मुद्दा है; लोगों के वरिध और सार्वजनिक प्रदर्शन अधकारियों पर कठोर रुख अपनाने का दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे समाधान प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

## जल वविादों को सुलझाने के लिये वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नयिम:

- हेलसंकी नयिम (Helsinki Rules) 1966:
  - व्यापक रूप से अनुपालति हेलसंकी नयिम के अनुच्छेद IV में अंतर्राष्ट्रीय अपवाह बेसनि के जल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में उपबंध कया गया है।
  - नयिमों के अनुसार, “प्रत्येक बेसनि राज्य, अपने कषेत्र के भीतर, एक अंतर्राष्ट्रीय अपवाह बेसनि के जल के लाभकारी उपयोग के संबंध में उचित और न्यायसंगत हसिसेदारी का हकदार है।”
  - हालाँकि, हेलसंकी नयिम का दायरा अंतर्राष्ट्रीय अपवाह बेसनि और इससे संबंधति भूजल स्रोतों तक ही सीमति था।
- जल संसाधन पर बरलिन नयिम (Berlin Rules on Water Resources), 2004:

- ये नयिम हेलसकिी नयिमों पर अधभिषी हुए और इनहोने राष्ट्रों के भीतर सभी ताज़े जल स्रोतों के उचित प्रबंधन; जलवायु संबंधी मुद्दे; पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करने; अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता देने और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल तक पहुँच के व्यक्तियों के अधिकार आदि पर बल दिया।

■ नोट:

- सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से जारी कावेरी जल विवाद पर कावेरी जल न्यायाधिकरण नरिणय, 2007 से उत्पन्न स्थिति पर वर्ष 2018 में नरिणय देते हुए चैंपियन रूलस (Carnegie Rules)—जो सतही जल और भूजल के बीच संपर्क को चिह्नित करता है, के साथ ही हेलसकिी नयिमों और बर्लनि नयिमों के सिद्धांतों का सहारा लिया था।

## संसाधनों के समान वितरण से किस प्रकार ISRWD का समाधान किया जा सकता है?

■ संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को समझना:

- स्थायी और स्वीकार्य समाधान पाने में प्राकृतिक संसाधनों का निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित उपयोग एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा।

- हालाँकि निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित उपयोग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इस अवधारणा का कार्यान्वयन कठिन सिद्ध हो सकता है।

- इस तरह के उपयोग को आमतौर पर कई कारकों के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो संबद्ध क्षेत्रों में इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों और सामाजिक स्थितियों पर निर्भर होते हैं।

- न्यायसंगत हिससेदारी इस प्रकार तय की जानी चाहिये कि प्रत्येक पक्ष जल के उपयोग में अधिकतम लाभ प्राप्त करे और दूसरे पक्ष को न्यूनतम हानि पहुँचाए।

■ हेलसकिी नयिमों से सहायता: हेलसकिी नयिमों में विचार किये जाने वाले प्रासंगिक कारकों का विस्तार से वर्णन किया गया है:

- कारकों के पहले समूह में प्रत्येक बेसनि राज्य के भीतर जल निकासी क्षेत्र, बेसनि में जल विज्ञान और जलवायु शामिल हैं। वे प्रत्येक राज्य के भीतर बेसनि जल संसाधनों का निर्धारण करेंगे।

- कारकों का दूसरा समूह प्रत्येक पक्ष द्वारा जल के उपयोग को निर्धारित करता है और स्पष्ट एवं वर्तमान उपयोग तथा प्रत्येक बेसनि राज्य में बेसनि के जल पर निर्भर आबादी को दायरे में लेता है।

- वैकल्पिक तरीकों से आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सापेक्ष लागत के साथ-साथ इन कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिये।

■ पर्याप्त जल डेटा:

- डेटा की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण न्यायसंगत वितरण का वैज्ञानिक निर्धारण कठिन सिद्ध हो सकता है।

- जैसा कि बर्लनि नयिम 2004 में अंतर्निहित है, जल संसाधनों से संबंधित जानकारी का उपलब्ध होना न्यायसंगतता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- इस प्रकार, सरकार को सभी प्रासंगिक जल संसाधन डेटा एकत्र करने और उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाने चाहिये।

■ अधिकतम लाभ के लिये सर्वोत्तम अभ्यास:

- जल का न्यायसंगत उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने और दूसरे पक्ष को न्यूनतम हानि पहुँचाने के लिये राज्यों को सर्वोत्तम जल उपयोग अभ्यासों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने की आवश्यकता है।

- भूजल के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि इससे नदियों के आधार प्रवाह में गिरावट आती है।

- राज्यों को कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

■ स्थानीय लोगों की भागीदारी:

- वर्तमान में आम लोगों की (जो अंतिम हितधारक हैं) की विवाद समाधान में कोई भागीदारी नहीं है क्योंकि न्यायाधिकरण केवल वाद में शामिल राज्यों के आधिकारिक प्रतिनिधियों की ही बात सुनते हैं।

- नागरिक समाज से प्राप्त इनपुट पर पारदर्शी तरीके से विचार करने के लिये एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिये।

- सतत जल प्रबंधन में सुशासन की स्थिति, लैंगिक अंतराल को समझकर और विशिष्ट बाधाओं को दूर करके सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है।

**अभ्यास प्रश्न:** अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने में वदियमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करते हुए इस मुद्दे के समाधान हेतु जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के महत्त्व का आकलन कीजिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

**प्रश्न.** अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान करने से संबंधित सांघिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजिये। (2013)

